MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION BHOPAL (M.P)

Unit -1

Course:PGDCA- II Semester

Subject: - IT Trends & Technologies

Paper code: 2PGDCA1

Que 1. ई-गवर्नेंस क्या हैं?

Ans 1. ई-गवर्नेंस का मतलब सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना| जिससे सरकारी कार्योलयों और जनता दोनों के पैसे और समय की बचत हो सके, और बार बार आपको विभिन्न दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े| सीधे शब्दों में कहें तो इ गवर्नेंस के तहत सभी सरकारी कामकाजों को ऑनलाइन कर दिया गया है जिससे जनता घर बैठे विभिन्न कार्यों के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सके| सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई-गवर्नेंस या ई-शासन कहलाता है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएँ और सूचनाएँ ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना जैसे नेशनल इंफ़ॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) की स्थापना ई-शासन की दिशा में पहला कदम था।

ई-गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाले कार्य एवं सेवाए !

1.आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिये सभी बेकिंग सेवाओ का लाभ उठा सकते हैं|

2.GST से सम्बंधित सभी कार्य ऑनलाइन ही कर सकते हैं|

3.बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल, DTH इत्यादि के बिल ऑनलाइन भरे जा सकते हैं|

4.PAN कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, जाती प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन|

5.आयकर रिटर्न फाइलिंग के सभी कार्य ऑनलाइन किये जा सकते हैं|

6.ट्रेन, बस और हवाई जहाज की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं|

Que 2. E-governance के प्रकार कया है !

Ans 2. E-governance 4 प्रकार की होती है और चारो की एक अलग प्रणाली तथा कार्य श्रंखला होती है| जिसके तहत वह कार्य करती है, इसमे एक पूरा System बना होता है, जो उदेश्य प्राप्ति के लिए मदद करता है| इसके प्रकार कुछ इस प्रकार है:-

1. G2G (Government to Government):- जी 2 जी यानी सरकार से सरकार, जब सूचना और सेवाओं का आदान-प्रदान सरकार की परिधि में होता है, इसे जी 2 जी इंटरैक्शन कहा जाता है| यह विभिन्न सरकारी संस्थाओं और राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के बीच और इकाई के विभिन्न स्तरों के बीच कार्य करता है।

2. G2C (Government to Citizen):- जी 2 सी यानी सरकार से नागरिक, यह सरकार और आम जनता के बीच बातचीत को जी 2 सी कहते है। यहां एक प्रकिया सरकार और नागरिकों के बीच स्थापित कि गई है, जिससे नागरिक विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। नागरिकों को किसी भी समय, कहीं भी सरकारी नीतियों पर अपने विचारों और शिकायतों को साझा करने की स्वतंत्रता है।

3. G2B (Government to Business):- जी 2 बी यानी सरकार से व्यवसाय, इसमे ई-गवर्नेंस बिजनेस क्लास को सरकार के साथ सहज तरीके से बातचीत करने में मदद करता है। इसका उद्देश्य व्यापार के माहौल में और सरकार के साथ बातचीत करते समय पारदर्शिता स्थापित करना है।

4. G2E (Government to Employees):- जी 2 ई यानी सरकार से कर्मचारी, किसी भी देश की सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता है और इसलिए वह नियमित आधार पर कर्मचारियों के साथ काम करती है, यह सरकार और कर्मचारियों के बीच कुशलता और तेजी से संपर्क बनाने में मदद करता है, साथ ही उनके लाभों को बढ़ाकर उनके संतुष्टि स्तर तक पहुँचाने में मदद करता है|

Que 3. ई-गवर्नेंस कि आवस्यकता क्या हैं ?

Ans 3. विभिन्न शोध अध्ययनों में यह स्पष्ट है कि ई-गवर्नेंस मौलिक रूप से कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर और संचार प्रणालियों की नेटवर्किंग के विकास से जुड़ा हुआ है। भारत में ई-गवर्नेंस की शुरुआत चार चरणों से हुई

1. कम्प्यूटरीकरण (Computerization): पहले चरण में, व्यक्तिगत कंप्यूटर की उपलब्धता के साथ सभी सरकारी कार्यालय में पर्सनल कंप्यूटर स्थापित किये गए| कंप्यूटर का उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग के साथ शुरू हुआ, इसके बाद डेटा प्रोसेसिंग में तेजी आई।

2. नेटवर्किंग: इस चरण में, कुछ सरकारी संगठनों की कुछ इकाइयाँ को विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान और डेटा के प्रवाह के लिए एक हब के माध्यम से जोड़ा गया।

3. ऑन-लाइन उपस्थिति (On-line presence): तीसरे चरण में, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ, वेब पर उपस्थिति बनाए रखने के लिए एक आवश्यकता महसूस की गई। इसके परिणामस्वरूप सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं द्वारा वेबसाइटों का रखरखाव किया गया। आम तौर पर, इन वेब-पृष्ठों / वेब-साइटों में संगठनात्मक संरचना, संपर्क विवरण, रिपोर्ट और प्रकाशन, संबंधित सरकारी संस्थाओं के उद्देश्य और दृष्टि विवरण के बारे में जानकारी होती थी।

4. ऑनलाइन अन्तरक्रियाशीलता (Online interactivity): ऑन-लाइन उपस्थिति का एक स्वाभाविक महत्व सरकारी संस्थाओं और नागरिकों, नागरिक समाज संगठनों आदि के बीच संचार चैनलों का खोला जाना था। इस चरण का मुख्य उद्देश्य डाउनलोड करने योग्य फॉर्म प्रदान करके सरकारी संस्थाओं के साथ व्यक्तिगत इंटरफ़ेस के दायरे को कम करना था।

Que 4. ई-गवर्नेंस के advantages क्या हैं ?

Ans ई-गवर्नेंस के निम्नांकित advantages हैं :

1. ई-गवर्नेंस शासन में सुधार है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के संसाधन उपयोग द्वारा सक्षम है।

2. ई-गवर्नेंस सभी नागरिकों के लिए सूचना और उत्क्रिस्ट सेवाओं की बेहतर पहुंच बनाता है।

3. यह सरकार में सरलता, दक्षता और जवाबदेही भी लाता है।

4. आईसीटी के उपयोग के माध्यम से शासन को व्यापक व्यापार प्रक्रिया के साथ संयुक्त रूप से पुनर्व्यवस्थित करने से जटिल प्रक्रियाओं का सरलीकरण, संरचनाओं में सरलीकरण और विधियों और नियमों में बदलाव होगा।

5. ई गवर्नेंस नागरिकों और सरकार के लिए लाभप्रद है क्योंकि संचार प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हो रहा है और शासन में इसे अपनाने से सरकारी मशीनरी को नागरिकों के घर-द्वार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

Que 5 डेमोक्रेसी क्या हैं ?

Ans 5. 'लोकतंत्र' शब्द का अंग्रेजी पर्याय 'डेमोक्रेसी' (Democracy) है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक मूल शब्द 'डेमोस' से हुई है | डेमोस का अर्थ होता है – 'जन साधारण' और इस शब्द में 'क्रेसी' शब्द जोड़ा गया है, जिसका अर्थ 'शासन' होता है | इसप्रकार 'डेमोस+क्रेसी' से 'डेमोक्रेसी' शब्द की रचना हुई है | जैसा कि उत्पत्ति के आधार से ही स्पष्ट हो जाता है कि 'डेमोक्रेसी' शब्द का अर्थ होता है 'जनता का शासन' |

लोकतंत्र (शाब्दिक अर्थ “लोगों का शासन”, संस्कृत में लोक, “जनता” तथा तंत्र, “शासन”,) या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है। यह शब्द लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य दोनों के लिये प्रयुक्त होता है।

Que 6. E-Democracy क्या हैं ?

Ans 6.ई-डेमोक्रेसी (इलेक्ट्रॉनिक और लोकतंत्र शब्द का एक संयोजन), जिसे डिजिटल लोकतंत्र या इंटरनेट लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए 21 वीं सदी की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को शामिल करता है। यह सरकार का एक रूप है जिसमें सभी वयस्क नागरिकों को प्रस्ताव, विकास और कानूनों के निर्माण में समान रूप से भाग लेने के लिए पात्र माना जाता है। ई-लोकतंत्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को समाहित करता है|

E-Democracy की आवश्यकताएँ

ई-डेमोक्रेसी सामाजिक निर्माण में सभी वयस्क नागरिकों की भागीदारी से ही संभव हो पाया है, विभिन्न साइटों और विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी इंटरनेट साइटों, समूहों और सामाजिक नेटवर्क की एक विस्तृत विविधता के माध्यम से सामाजिक समावेश की एक संरचना भी प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत रूप से और तेजी से व्यक्तिगत राय व्यक्त करने की क्षमता के माध्यम से व्यक्ति की जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता को पूरा किया जाता है।

1. इंटरनेट का उपयोग - ई-लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सक्रिय प्रतिभागियों और इलेक्ट्रॉनिक समुदायों में भाग नहीं लेने वालों के बीच डिजिटल विभाजन से बाधित किया जाता है।

2. सुरक्षा और गोपनीयता की सुरक्षा – सरकार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऑनलाइन संचार सुरक्षित हो और वे लोगों की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं करते हों| किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है|

3. सरकारी जवाबदेही - ऑनलाइन परामर्श और चर्चाओं में शामिल होने के लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए, सरकार को लोगों को जवाब देना चाहिए और सक्रिय रूप से प्रदर्शित करना चाहिए कि सभी नागरिकों और नीतिगत परिणाम के बीच एक संबंध है।

Que 7. PPP Model क्या हैं ?

Ans 7. सार्वजनिक-निजी साझेदारी को PPP, 3P या P3 आदि नामो से जाना जाता हैं, इसमें दो या दो से अधिक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच एक सहकारी व्यवस्था है, जो आमतौर पर दीर्घकालिक प्रकृति की होती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरकार निजी कंपनियों के साथ अपनी परियोजनाओं को पूरा करती है। देश के कई हाईवे इसी मॉडल पर बने हैं। इसके द्वारा किसी जन सेवा या बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन की व्यवस्था की जाती है। इसमें सरकारी और निजी संस्थान मिलकर अपने पहले से निर्धारित लक्ष्य को पूरा करते हैं और उसे हासिल करते हैं।

पीपीपी एक व्यापक शब्द है जिसे एक सरल, अल्पकालिक प्रबंधन के किसी भी लंबी अवधि के अनुबंध के लिए लागू किया जा सकता है जिसमें धन, योजना, भवन, संचालन, रखरखाव और विनिवेश शामिल हैं। पीपीपी व्यवस्था बड़ी परियोजनाओं के लिए उपयोगी होती है जिन्हें शुरू करने के लिए अत्यधिक कुशल श्रमिकों और महत्वपूर्ण नकदी परिव्यय की आवश्यकता होती है। वे उन देशों में भी उपयोगी हैं जिन्हें राज्य को कानूनी रूप से किसी भी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है जो जनता की सेवा करता है।

PPP Model की जरूरत क्यों ?

पीपीपी की जरूरत इसलिए पड़ती है, क्योंकि जब सरकार के पास इतना धन नहीं होता है, जिससे वह अपनी हजारों करोड़ रुपयों की घोषणाओं को पूरा कर सके तब ऐसी स्थिति में सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करती हैं और इन परियोजनाओं को पूरा करती है।

पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे नए टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, एयरपोर्ट या पावर प्लांट के लिए फंडिंग मॉडल है। सार्वजनिक भागीदार का प्रतिनिधित्व सरकार द्वारा स्थानीय, राज्य और / या राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। निजी भागीदार एक निजी स्वामित्व वाला व्यवसाय, सार्वजनिक निगम या विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र के साथ व्यवसायों का संघ हो सकता है।

Que 8. एमपी ऑनलाइन सर्विसेज क्या हैं ?

Ans 8 एमपी ऑनलाइन सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुंचाने का एक सरल और सुरक्षित तरीका है| एमपी ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार की ई गवर्नेंस की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं को सीधे आम नागरिकों को घर बैठे उपलब्ध कराना है| एमपी ऑनलाइन लिमिटेड मध्य प्रदेश

सरकार एवं टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज (TCS) लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है| विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं को नागरिकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई 2006 में एमपी ऑनलाइन लिमिटेड पोर्टल का गठन किया था तब से मध्य प्रदेश सरकार प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर रही है

Que 9. UIDAI तथा आधार क्या हैं ?

Ans 9. Unique Identification Authority of India (UIDAI) नई दिल्ली में एक सरकारी एजेंसी है जो Aadhaar unique identification numbers (UIDs) और कार्ड के लिए जारी करने वाले प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है। सरकार द्वारा आधार कार्ड जारी करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास, पहचान और स्थापना के लिए एजेंसी को अनिवार्य किया गया है।

UIDAI को भारत सरकार द्ववारा स्थापित किया गया था जो भारत के योजना आयोग के हिस्से के रूप में कार्य करता है। एजेंसी, राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं और विभागों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम जैसी संस्थाओं से बनी कई रजिस्ट्रार एजेंसियों की मदद से कार्ड जारी करती है।

Que 10 उमंग एप्प क्या हैं ?

डिजिटल इंडिया के कदम को आगे बढ़ाने के लिए एक और पहल करते हुए, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने साइबरस्पेस पर वैश्विक सम्मेलन के 5 वें संस्करण में भारत के नागरिकों के लिए एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया हैं। इस एप्प का नाम उमंग है यह शब्द नए युग के शासन के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन के लिए है और इसे ई-गवर्नेंस बनाने की परिकल्पना की गई है। जो सभी एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज डिवाइस उपयोगकर्ताओं और फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। यह एक एप्लीकेशन है जो एक एक ही जगह पर केंद्र और राज्य सरकार की सेवाएं प्रदान करता है। इस ऑल-इन-वन ऐप का उपयोग करके आप केवल माउस क्लिक द्वारा सभी सरकारी संबंधित सेवाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। यूजर्स अलग-अलग भाषाओं में ऐप को एक्सेस कर कर सकते हैं।

उमंग पर उपलब्ध सर्विसेज :

1. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) सेवाएं: उमंग ऐप उपयोगकर्ताओं को कर्मचारी केंद्रित सेवाओं और सामान्य सेवाओं जैसे EPFO सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता दावे करने और अपनी स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम होंगे।

2. एलपीजी सेवाएं: उमंग ऐप का इस्तेमाल ऑनलाइन सिलेंडर बुक करने, रिफिल मांगने, सब्सिडी, सरेंडर कनेक्शन, मैकेनिक सेवाओं के लिए पूछने आदि के लिए किया जा सकता है। सेवाओं का लाभ भारत गैस, एचपी गैस और इंडेन गैस पर लिया जा सकता है।

3. कर भुगतान: उमंग ऐप के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह उपयोगकर्ताओं को आयकर की ओर भुगतान करने की भी अनुमति देता है।

4. पासपोर्ट सेवा: ग्राहक उमंग ऐप का उपयोग विभिन्न पासपोर्ट सेवा से संबंधित सेवाओं जैसे केंद्र का पता लगाने, शुल्क भुगतान की गणना, पासपोर्ट आवेदन की स्थिति पर नज़र रखने और नियुक्ति उपलब्धता की जांच करने के लिए कर सकते हैं।

5. पेंशन: सभी पेंशनभोगी पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ऐप पर पेंशन पोर्टल के माध्यम से सभी सुविधाएं जैसे पेंशन आवेदन प्रक्रिया, शिकायत, और सेवानिवृत्ति के अन्य लाभों का लाभ उठाया जा सकता है।

6. ePathshala: यह भारत सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCRT) की एक पहल है। छात्रों के पास ई-पुस्तकें, शैक्षिक ऑडियो, और वीडियो, समय-समय पर, सीखने के परिणाम आदि होंगे। इस सेवा का उपयोग शिक्षकों द्वारा शैक्षिक सामग्री और शिक्षण निर्देशों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है। माता-पिता भी उसी के लिए पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।

7. CBSE: छात्र अपने परिणामों की जांच करने और परीक्षा केंद्रों का पता लगाने के लिए इस ई-गवर्नेंस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। एक बटन के क्लिक पर उमंग ऐप का उपयोग करके 10 वीं / 12 वीं, CTET, NET और JEE परीक्षा के परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

8. e-Dhara Land Records: गुजरात के उपयोगकर्ता जिला तालुका और गांवों के संबंध में उमंग ऐप का उपयोग करके अपने भूमि रिकॉर्ड की जांच कर कर सकते हैं।

9. डिजी सेवा: ऐप उपयोगकर्ताओं को नौकरियों के लिए आवेदन करने और इस मंच का उपयोग करने के लिए एक ही उद्देश्य के लिए अपनी प्रोफाइल बनाने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता सरकारी संगठनों द्वारा पोस्ट किए गए सभी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

10. फसल बीमा: सभी किसान इस टूल का उपयोग बीमा प्रीमियम की गणना करने के लिए कर सकते हैं।

11. फार्मा साही डैम: यह एप्लिकेशन उपयोगकर्ता को दवाओं के लिए search tool का उपयोग करके कीमतों की तलाश करने की अनुमति देता है।

12. ड्राइविंग लाइसेंस: वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्रों पर एक नज़र डालने और उसे डाउनलोड करने के लिए भी उपयोगकर्ता Parivahan Sewa -Sarathi और Vahan का उपयोग कर सकेंगे।

Que 11 Write short note:-

A. Digital Locker

भारत सरकार ने नागरिकों को पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट और डिग्री प्रमाणपत्र जैसे अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप से संग्रहीत करने में मदद करने के लिए डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू की। यदि आप आधार नंबर से जुड़े हैं तो आप दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं, आरसी कॉपी जैसे जारी किए गए दस्तावेज़ प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा पाने के लिए बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड का नंबर डालकर आप डिजीटल लॉकर अकाउंट खोल सकते हैं।

इस सर्विस की सबसे खास बात यह है कि आप कहीं भी कही भी अपने दस्तावेज को डिजिटल लॉकर द्वारा उपयोग कर सकते हैं अब आपको बार-बार कागजों का प्रयोग नहीं करना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (डीईआईटीवाई) ने हाल ही में डिजिटल लॉकर का बीटा वर्जन लॉन्च किया है।

Uses of Digital Locker (डिजिटल लॉकर के उपयोग):

1. नागरिक अपने डिजिटल दस्तावेजों को कभी भी, कहीं भी ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। यह सुविधाजनक होता हैं और समय की बचत भी करता है।

2 .यह कागज के उपयोग को कम करके सरकारी विभागों के प्रशासनिक भार को कम करता है।

3. डिजिटल लॉकर दस्तावेजों की प्रामाणिकता को मान्य करना आसान बनाता है क्योंकि वे सीधे जारी किए गए जारीकर्ताओं द्वारा जारी किए जाते हैं।

4. स्व-अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप से eSign सुविधा (जो कि स्व-सत्यापन की प्रक्रिया के समान है) का उपयोग करके हस्ताक्षरित किया जा सकता है।

B. Digital Library

डिजिटल लाइब्रेरी एक पुस्तकालय है जिसमें डाटा डिजिटल स्वरूपों (जैसे कि प्रिंट, माइक्रोफ़ॉर्म, या अन्य मीडिया के विपरीत) में स्टोर होता हैं और कंप्यूटर द्वारा एक्सेस किया जा सकता हैं। कंटेंट को स्थानीय रूप से स्टोर किया जा

सकता है, या दूरस्थ रूप से एक्सेस किया जा सकता है। इस शब्द को पहली बार। डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव द्वारा लोकप्रिय किया गया था।

C.BHIM APP

भीम ऐप (BHIM-Bharat Interface for Money) वित्तीय लेनदेन हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरम्भ किया गया एक मोबाइल ऐप है। इस ऐप का तन्त्रांश बिना अंतरजाल के प्रयुक्त किया जा सकता है! अभी यह ऍप केवल हिन्दी व अंग्रेज़ी भाषा में एंड्रॉइड प्रचालन तंत्र के लिए उपलब्ध है, परंतु शीघ्र ही अन्य भारतीय भाषाओं एवं आईओएस के लिए इसका विमोचन किया जाएगा भविष्य में दूरभाष या अंतरजाल संयोजकता के बिना भी इसका उपयोग लेनदेन के लिए किया जा सकेगा।

Que 12. साइबर क्राइम क्या है ?

यह ऐसा कार्य है जो गैर कानूनी है, तथा जिसमें सूचना तकनीक या कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है| आधुनिक युग में बहुत से गैरकानूनी काम या अपराध करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जैसे चोरी धोखाधड़ी जालसाजी शरारत आदि| सूचना तकनीकी प्रगति ने अपराधिक गतिविधियों के लिए नई संभावनाएं भी बनाए हैं, इन प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए साइबर लॉ बनाया गया है| साइबर क्राइम को दो तरीकों में बांटा जा सकता है।

साइबर क्राइम के प्रकार (Types of Cyber Crime)

किसी कंप्यूटर को निशाना बनाना –

इस प्रकार में किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क को अवांछित तरीके से कब्जा करना|

किसी वेबसाइट के घटक बदलना|

किसी कंप्यूटर पर वायरस डालना आदि शामिल है।

कंप्यूटर का प्रयोग कर अपराध करना –

इस प्रकार के अपराधों में व्यक्ति या संस्था को कंप्यूटर का प्रयोग कर नुकसान पहुंचाया जाता है|

इस प्रकार में किसी अनैतिक जानकारियों को लोगों तक पहुंचाना भी शामिल है|

साइबर आतंकवाद बैंक अकाउंट से धोखाधड़ी|